रसायन और उर्वरक स्थायी समिति की चेयरपर्सन (2019-20) श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के "उर्वरक सब्सिडी की प्रणाली का अध्ययन" विषय पर आज पांचवीं रिपोर्ट लोकसभा में पेश की।

उर्वरक सब्सिडी नीति	समिति की सलाह देते हैं एड कि सरकार की उर्वरक सब्सिडी नीति देश और नीति में किसी भी भारी परिवर्तन के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में देश की मदद की केवल व्यापक विचार-विमर्श के बाद और गहराई से अध्ययन और कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय में में लिया जाना चाहिए प्रभावित किया जाना चाहिए इस संबंध में। अन्य देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा उर्वरक सब्सिडी नीति में किसी भी बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए ।
किसानों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण	समिति ने महसूस किया कि सरकार को उर्वरकों की वर्तमान प्रणाली से एक ऐसी प्रणाली के लिए स्विच करने के लिए एक स्पष्ट और दृढ़ रोडमैप स्थापित करने का समय आ गया है, जहां सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा हो और विनिर्माण / आयात हो उर्वरक बाजार की ताकतों के लिए स्वतंत्र हैं।
सब्सिडी पर खर्च करने के लिए अभिनव तरीके	समिति की सलाह देते हैं एड कि सरकार हर संभव कदम उठाने चाहिए सबसे अच्छा विनिर्माण प्रथाओं, सख्त ऊर्जा कसौटियों को अपनाने से उर्वरक सब्सिडी पर होने वाले खर्च को कम करने के , तो विनिर्माण संयंत्रों उर्वरकों के आधुनिकीकरण के रूप में उर्वरकों के उत्पादन लागत कम करने के लिए इस तरह उर्वरक सब्सिडी खर्च को कम करने के सरकार।
सब्सिडी दावों और कैरी-फॉरवर्ड देनदारियों के निपटान में देरी	समिति दृढ़ता से अनुशंसा करते एड कि विभाग एक प्रणाली है जिसके द्वारा दावे की राशि का एक निश्चित अनुपात पाँच कार्यकारी दिनों की अवधि के भीतर स्वचालित रूप से निर्माण करने के लिए भुगतान किया जाता है विकसित करनी चाहिए। यह राशि सब्सिडी के कुल दावे का 75% हो सकती है। विभाग को नीति निर्देशों के तहत निर्धारित 7 दिनों के भीतर DBT के तहत सब्सिडी के दावों के निपटान के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए।
नई निवेश नीति	समिति की सलाह देते हैं एड कि नई निवेश नीति (NWP 2012) के प्रावधानों इतनी के रूप में उपयुक्त संशोधन के लिए दोबारा गौर किया जाना चाहिए यूरिया उत्पादन में निजी निवेश को आकर्षित करने के। निर्धारित समय अवधि के भीतर सिंदरी, गोरखपुर, तालचेर, रामागुंडम में आगामी यूरिया संयंत्रों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए , ताकि आयात का सहारा लिए बिना घरेलू स्तर पर यूरिया की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ।
यूरिया सब्सिडी नीतियों में लगातार बदलाव	समिति की सिफारिश की उर्वरक सब्सिडी नीतियों में है कि लगातार परिवर्तन से बचा जा सकता है और कहा कि उर्वरक सब्सिडी नीतियों उर्वरक उद्योग और सरलीकृत लागू करने के लिए किसानों के प्रतिनिधियों, सुव्यवस्थित और प्रभावी उर्वरक सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श गहराई से अध्ययन में जाने के बाद ही संशोधन होना चाहिए सब्सिडी नीतियों।
उर्वरक उद्योग के लिए गैस के आवंटन की मात्रा	समिति की सलाह देते हैं एड कि उर्वरक विनिर्माण उद्योग के लिए आवंटित गैस की पूरी मात्रा प्रदान की जानी चाहिए करने के लिए सरकार द्वारा RNLG के आयात से दूर वार्ड। उर्वरक विभाग को इस संबंध में उच्चतम स्तर पर संबंधित मंत्रालय के साथ समस्या उठानी चाहिए और इस समिति द्वारा की गई सिफारिश को भी अनुपालन के लिए अवगत कराना चाहिए ।
फ्रेट सब्सिडी	समिति की सिफारिश की है, ताकि बकाया गणना अभ्यास परहेज कर रहे हैं और सब्सिडी का दावा है और भुगतान वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा कर रहे हैं और अगले करने के लिए नहीं अग्रेषित का वाहक हैं एक वर्ष के लिए प्राथमिक आंदोलन के लिए वार्षिक PTPK स्लैब दरों वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले अधिसूचित किया जा सकता संशोधित दरों के लिए वित्तीय वर्ष। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं कि रिटेल-बिक्री की सुविधा सभी रेल-रेक-पॉइंट्स पर उपलब्ध हो, जहाँ भी आवश्यक हो, नए रिटेल-आउटलेट्स / मॉडल फ़र्टिलाइज़र दुकानें खोल सकते हैं।

किसानों को उर्वरकों की बिक्री की प्रणाली	समिति की सलाह देते हैं एड कि विभाग निर्देश है कि खुदरा उनके हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान और सत्यापन उद्देश्यों के लिए उनमें से प्रत्येक के लिए आवश्यक उर्वरकों की मात्रा के साथ-साथ किसानों की सूची प्राप्त कर सकते हैं जारी कर सकता है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया जा सकता है कि वे सब्सिडी वाले उर्वरक के विचलन / दुरुपयोग पर निगरानी रखें और इस उद्देश्य के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। यह भी सिफारिश की गई थी कि उर्वरक विभाग सब्सिडी वाली उर्वरकों के किसी भी संभावित दुरुपयोग का पता लगाने के लिए इस संबंध में गतिविधियों की यादृच्छिक जांच कर सकता है ।
फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की निगरानी	समिति की सलाह देते हैं एड है कि सभी पी एंड कश्मीर उर्वरक कंपनियों की लागत डेटा राजनीति उनके सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करने और आवश्यक कार्रवाई के समय उन कंपनियों जो पी एंड कश्मीर उर्वरकों के मूल्य को लेकर में लिप्त के खिलाफ लिया जाना चाहिए पर जांच की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई थी कि उर्वरक विभाग एमआरपी से ऊपर और 12% से अधिक कंपनियों द्वारा उर्वरकों पर अर्जित लाभ की वसूली के लिए दिशानिर्देशों को जल्दी से अंतिम रूप दे और अनुचित पाया जाए और दिशानिर्देशों के प्रावधानों को समयबद्ध तरीके से लागू करें।
आयातित पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी	समिति ने सिफारिश की कि उर्वरक विभाग अंतरराष्ट्रीय बाजार में और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंबे समय से प्रचलित पी एंड कश्मीर उर्वरकों के लिए सस्ता लागत मूल्य के मामले में पी एंड कश्मीर उर्वरकों के लागत मूल्य की निगरानी के लिए जारी रखा के लिए कदम उठाएगा, आवश्यक कदम की रक्षा के लिए ले जाया जा मौजूदा घरेलू कंपनियों के हित ।
शहर के खाद को बढ़ावा देने के लिए योजना	समिति की सलाह देते हैं एड कि विभाग में अच्छी तरह से एक अंतर-मंत्री स्तरीय शरीर कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण, आवास और शहरी विकास, पेयजल मंत्रालय के शामिल और स्वच्छता का गठन के रूप में उर्वरक विभाग के लिए एक स्पष्ट रोडमैप सेटअप करने के लिए बड़े पैमाने पर शहर के खाद प्रणालियों का विस्तार करना और किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से अपने कृषि के लिए खाद का उपयोग करने के लिए स्थानांतरित करना। समिति की सलाह घ विभाग तुरंत राष्ट्रीय हित में इस मुद्दे को उठाने और इसकी सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिए इस अंतर-मंत्रालय समिति के लिए महीने छह से अधिक नहीं की समय सीमा निर्धारित करने के लिए ।
मृदा विशिष्ट उर्वरकों के उपयोग के लिए किसानों को शिक्षा	समिति की सलाह देते हैं एड कि विभाग अप लेना चाहिए विषय को शिक्षित मिट्टी विशिष्ट के उपयोग के लिए किसानों को उर्वरक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ और कार्रवाई की एक फर्म की योजना के साथ आने के लिए इतना है कि अलग-अलग किसानों द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग टी पर युक्तिसंगत हो जाता है उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की पहचान करने के लिए कदम उठाए हैं, जहां विशेष रूप से यूरिया का उपयोग किसानों द्वारा 4: 2: 1 के वांछनीय एनपीके अनुपात के खिलाफ बहुत ही विकृत अनुपात में किया जाता है। । इसके अलावा, उर्वरकों के लिए वार्षिक मांग के प्रक्षेपण के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को बहुत अधिक मात्रा में सब्सिडी वाले उर्वरकों की आपूर्ति को रोकने के लिए उपयुक्त निवारक तंत्र विकसित किया जा सकता है । मृदा विशिष्ट उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में किसानों को उचित सलाह देने के लिए किसान कॉल सेंटर (KCC) भी शामिल हो सकते हैं